भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2524
दिनांक 10 अगस्त 2026

एआईडीए द्वारा एथेनॉल की आपूर्ति का प्रस्ताव

2524 **श्री गोला बाबूरावः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (एआईडीए) ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रण के लिए और अधिक एथेनॉल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) क्या इसका यह आशय है कि सरकार, एआईडीए के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की स्थिति में, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है;

(ग) घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए एथेनॉल पर चलने वाले चूल्हों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार लागत को नियंत्रित करने के लिए डीजल में भी एथेनॉल का मिश्रण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिकाधिक समर्पित डिस्टिलरियों को अनुमति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अपने पंजीकृत इथेनॉल उत्पादकों से इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) के लिए इथेनॉल मात्रा बोलियों की मांग करते हुए इथेनॉल अधिप्राप्ति हेतु निविदाएं जारी करती हैं। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए लगभग 1050 करोड़ लीटर इथेनॉल अधिप्राप्ति के लिए पहला निविदा चक्र सितंबर 2025 के दौरान जारी किया गया था, जिसके सापेक्ष लगभग 1760 करोड़ लीटर (यानी 68% अधिक) की पेशकश प्राप्त हुई थी। ओएमसीज ने तब से इथेनॉल के 378 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को 1048.5 करोड़ लीटर आवंटित किया है, जिसकी आपूर्ति ईएसवाई 2025-26 की सभी तिमाहियों के दौरान की जाएगी। अखिल भारतीय डिस्टिलर्स एसोसिएशन (एआईडीए) इथेनॉल का पंजीकृत आपूर्तिकर्ता नहीं है।

पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 20% से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इथेनॉल के उच्चतर मिश्रण के संबंध में भविष्य में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद ही लिया जाएगा।

(ग): इथेनॉल का खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग, जीवाश्म ईंधन आधारित खाना पकाने के समाधान के संभावित जैव ईंधन विकल्प के रूप में हो सकता है, जो एलपीजी आयात निर्भरता को कम करने और स्वच्छ खाना पकाने का समाधान प्रदान करने में सहायता कर सकता है। यह देश में अधिशेष इथेनॉल उत्पादन क्षमता के प्रभावी उपयोग को भी सक्षम कर सकता है। विषय के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए, एलपीजी उपकरण अनुसंधान केंद्र (एलईआरसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का एक संयुक्त उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के साथ मिलकर इथेनॉल आधारित स्वच्छ खाना पकाने के विकल्पों की दिशा में विकास के प्रयास कर रहा है। यह पहल स्वच्छ और वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधन विकल्पों को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।

(घ): हाँ। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और ऑटोमोबाइल निर्माताओं के सहयोग से अपने-अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के माध्यम से डीजल के साथ इथेनॉल के मिश्रण पर वैज्ञानिक मूल्यांकन किए गए हैं। यह देखा गया कि इथेनॉल मिश्रित डीजल, डीजल के फ्लैश पॉइंट को पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि इथेनॉल की उपस्थिति के कारण इसका फ्लैश पॉइंट काफी कम हो गया था।

(ङ): सरकार ने देश भर में इथेनॉल के उत्पादन का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न इथेनॉल ब्याज सहायता योजनाएं (ईआईएसएस) की शुरुआत करना, सहकारी चीनी मिलों के लिए मौजूदा गन्ना-आधारित डिस्टिलरी को शीरे के साथ-साथ अनाज से इथेनॉल उत्पादन के लिए बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में बदलने के लिए एक समर्पित सहायता योजना की शुरुआत करना, ओएमसी और समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक ऑफटेक समझौते (एलटीओए) करना आदि शामिल हैं।

*****